

विशेष न्यायालय (एस०सी०/एस०टी० एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायालय, कोर्ट संख्या:- 02, उन्नाव

UPUN010029592026



प्रकीर्ण वाद संख्या:- 225/2026

रोहित कुमार बनाम ललित आदि

दिनांक:- 03.07.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार लगाई गई।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा:- 173(4) बी०एन०एस०एस० में कथन किया गया है कि प्रार्थी उपरोक्त पते का निवासी है तथा प्रार्थी एक अनुसूचित जाति (पासी) का व्यक्ति है तथा विपक्षीगण जो कि प्रार्थी के गांव के ही मूल निवासी है तथा अनुसूचित जाति के व्यक्ति नहीं है। घटना दिनांक 10.04.2026 की रात करीब 8.30 बजे की है जब प्रार्थी गांव के ही प्रेम शंकर लोधी की दुकान पर सामान लेने के लिए जा रहा था तभी रास्ते में विपक्षीगण 1 ता 4 ने प्रार्थी को घेर लिया और गंदी गंदी जाति सूचक गालियाँ देने लगे जब प्रार्थी ने विरोध किया तो सभी लोगों ने प्रार्थी को लात घूसों व डन्डों से बहुत मारा पीटा। प्रार्थी ने शोर मचाया तो गांव के लोग बचाने दौड़े तभी सब लोग प्रार्थी को जान से मारने की धमकी देकर चले गये। प्रार्थी को काफी चोटें आयी है तथा प्रार्थी के दाहिने कन्धे की हड्डी भी टूट गयी है। प्रार्थी ने घटना की शिकायत दिनांक 11.04. 2026 को थाना मौरावा में प्रार्थना पत्र देकर की तब पुलिस ने दूसरे दिन बुलाया प्रार्थी पुनः दिनांक 12.04.2026 को थाना मौरावा गया तब पुलिस ने प्रार्थी का मेडिकल कराया। डाक्टर ने एक्सरे कराने हेतु जिला अस्पताल रेफर किया तब प्रार्थी थाना मौरावा में कार्यरत सिपाही सीताराम के साथ जिला अस्पताल गया वहां पर प्रार्थी का एक्सरे हुआ जिसमें फ्रैक्चर पाया गया बावजूद इसके थाना मौरावा की पुलिस ने आज तक रिपोर्ट दर्ज नहीं की और ना ही प्रार्थी को मेडिकल रिपोर्ट की कापी दी। इसके बाद दिनांक 22.04.2026 को प्रार्थी ने जनसुनवाई पोर्टल के माध्यम से एस०डी०एम० पुरवा उन्नाव डी०एम० उन्नाव व डी०जी०पी० उत्तर प्रदेश व मा० मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश व महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश को शिकायती पत्र प्रेषित किये परन्तु अभी तक कोई सुनवायी नहीं हुयी। इसके बाद प्रार्थी ने पुनः दिनांक 27.04.2026 को उन्नाव जाकर पुलिस अधीक्षक उन्नाव को स्वयं उपस्थित होकर तथा जरिये रजिस्टर्ड डाक प्रार्थना पत्र देकर घटना की शिकायत की परन्तु अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुयी तब प्रार्थी मा० न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दे रहा है। अतः मा० न्यायालय से प्रार्थना है कि प्रार्थी की रिपोर्ट दर्ज कर अपराध की घटना की जांच करने हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना मौरावा को आदेशित करने की कृपा करें।

आवेदक के द्वारा अपने प्रार्थना-पत्र के साथ आवश्यक प्रपत्र दाखिल किए गए हैं।

संबंधित थाना मौरावां से आख्या तलब की गई। थाना से प्राप्त आख्या के अनुसार प्रार्थना-पत्र में अंकित आरोपों के सम्बन्ध में थाना हाजा पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है और ना ही विवेचना प्रचलित है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों एवं आख्या का अवलोकन किया।

धारा:- 156(3) दं०प्र०सं० के निस्तारण के सम्बन्ध में नजीर Mrs Priyanka Srivastava and others Vs State of U.P. and others 2015 AIR SCW 2075 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह मत अभिप्रकट किया है कि मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्राधिकार के भीतर उपयुक्त मामले में तथ्य की जांच हेतु अधिकृत है जिसके लिए यह शपथ-पत्र लेकर कार्यवाही करेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि तथ्यों की जांच करते समय आरोप के प्रकार पर विचार किया जाए क्योंकि अधिकांश मामले वैवाहिक, पारिवारिक मतभेद, वाणिज्यिक मतभेद, भ्रष्टाचार, चिकित्सीय उपेक्षा से सम्बन्धित होते हैं और ऐसे मामलों को बढ़ा चढ़ाकर विधिपूर्ण तरीके से तैयार कर न्यायालय में प्रेषित किया जाता है। उपरोक्त विनिश्चय में माननीय न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि प्रार्थना-पत्र में दिए गए तथ्य की विश्वसनीयता को परखते हुए न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए धारा:- 156(3) दं०प्र०सं० के प्रार्थना-पत्र पर विचार करना चाहिये एवं मापदण्डों के अनुरूप ही उक्त पर आदेश पारित करना चाहिये।

विधि व्यवस्था जोजेफ माधुरी उर्फ विशेश्वरी नन्दा आदि बनाम स्वामी सच्चिदानन्द हरिसाक्षी आदि सुप्रीम कोर्ट 2001 (Suppl.) A.C.C. पृष्ठ 951, सुरेश चन्द्र जैन-बनाम-मध्य प्रदेश राज्य ए.आई.आर. 2001 Supreme Court पेज 571, मोहम्मद युसुफ-बनाम-आफाक जहाँ व अन्य 2006 (1) एस.सी.सी.(फौज.) पेज 1460 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि धारा:- 156(3) दं०प्र०सं० के प्रार्थना-पत्र को परिवाद के रूप में दर्ज किया जा सकता है।

इसी संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा Naresh Kumar Valmiki v. State of U.P., Application under Section 482 No. 14443 of 2022 dated 17.10.2022, wherein Division Bench of Hon. Allahabad High Court held that Exclusive Special Court or Special Court under the SC/ST Act, 1989 can treat an application under Section 156(3) of Cr.P.C., as a complaint.

इसी संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ओम प्रकाश अम्बेडकर बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य 2025 Live law (S.C.) 139 में भी कथन किया गया है कि the allegations made in the complaint are simple, where the Court can straightaway proceed to conduct the trial, the Magistrate is expected to record evidence and proceed further in the matter, instead of passing the buck to the Police under Section 156(3) of the Cr.P.C. Ofcourse, if the allegations made in the complaint require complex and complicated investigation

which cannot be undertaken without active assistance and expertise of the State machinery, it would only be appropriate for the Magistrate to direct investigation by the police authorities. The Magistrate is, therefore, not supposed to act merely as a Post Office and needs to adopt a judicial approach while considering an application seeking investigation by the Police.”

उपरोक्त विधि व्यवस्था के अनुक्रम में प्रार्थना-पत्र के अवलोकन से विदित होता है कि घटना दिनांक 10.04.2026 को रात करीब 8.30 बजे जब प्रार्थी गांव के ही प्रेम शंकर लोधी की दुकान पर सामान लेने के लिए जा रहा था तभी रास्ते में उक्त विपक्षीय द्वारा प्रार्थी को घेरकर गंदी-गंदी जाति सूचक गालियाँ देने व प्रार्थी के विरोध करने पर सभी लोगों द्वारा प्रार्थी को लात-घूसों व डन्डों से मारने-पीटने तथा प्रार्थी को जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है। आवेदक को प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र में अभियुक्त के नाम व विवरण तथा साक्षियों के साक्ष्य की भी जानकारी है। विवेचना से किसी नए तथ्य के उद्भूत होने की कोई सम्भावना नहीं है। अतः आवेदक प्रार्थना-पत्र में किए गए तथ्यों के बाबत साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है।

प्रार्थना-पत्र में दर्शित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय प्रस्तुत मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में प्रकरण को परिवाद के रूप में दर्ज कर जाँच प्रक्रिया का अनुसरण करके आदेशिका पर विचार किया जाना न्यायोचित पाती है।

आदेश

प्रस्तुत प्रकरण परिवाद के रूप में दर्ज हो। तद्विषय प्रकीर्ण वाद निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली वास्ते बयान परिवादी अन्तर्गत धारा:-223 बी०एन०एस०एस० दिनांक 07.09.2026 को पेश हो।

दिनांक:- 03.07.2026

(अंकिता शुक्ला)
विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी० एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या:-02, उन्नाव